भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली 21.07.2017

<u>प्रैस विज्ञप्ति</u>

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 20 भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक संसद मे पेश किया गया

प्रतिवेदन के बारे में

वर्ष 2015-16 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,43,534 करोड़ था। इसमें से, नौसेना ने ₹35,196 करोड़ खर्च किए जबकि तटरक्षक ने ₹3,034 करोड़ खर्च किए, जो की कुल रक्षा व्यय का लगभग क्रमशः14.45 प्रतिशत तथा 1.25 प्रतिशत था। नौसेना के व्यय का मुख्य भाग पूंजीगत स्वरूप (56.47 प्रतिशत) का है, जबकि तटरक्षक का कुल व्यय पूंजीगत एवं राजस्व शीर्षों के बीच समान रूप से प्रत्येक के लिए ₹1,517 करोड़ वितरित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में शामिल भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक के लेन-देन की लेखापरीक्षा से उद्भूत मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये है:

I.	**भारतीय नौसेना में नौसेना भण्डारतथाउपकरण एवं अतिरिक्त पुर्ज़ोंकेइन्वेंट्री प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

सामग्री नियोजन में जिम्मेदारी के कई क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, इन्वेंट्री प्रबंधन और मुद्दा प्रबंधन हैं। इन्वेंट्री वहन की लागत को कम करने के लिए अच्छी इन्वेंट्री प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एकीकृत रसद प्रबंधन तंत्र, जो एक ऑन-लाइन, डेटा से जुड़े कंप्यूटर तंत्रद्वारा नौसेना की सामग्री नियोजन का समर्थन करता है।

प्रणाली आधारित प्रोविज़निंग फार्मूला द्वारा सृजित अधिप्राप्ति मात्रा अधिक थी तथा अनुमानित मात्रा, विद्यमान फार्मूले में बीजगणितीय विसंगति के कारण तीन से छः वर्षों के वार्षिक उपभोग की आवश्यकता के समान थी। भारतीय नौसेना में इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म की कमी इस सीमा तक है कि एबीसी वर्गीकरण मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। यह इन्वेंट्री के अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक स्तर की समीक्षा प्रावधान और मूल्यांकन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। मांगपत्रों के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं किया गया था जो भंडारों की खरीद में व्यापक प्रभाव का कारण था। मालिकाना हक प्रमाण पत्र और एकल संविदा जांच के तहत खरीदी गई मदें,खुली निविदा पूछताछ और दर संविदाओं के तहत खरीदे गए मदों की तुलना में काफी अधिक थे, जिससे कम प्रतिस्पर्धा/एकाधिकार की स्थिति हो गई थी। ₹46.92 करोड़ की अप्रचलित मदों की खरीद का निर्णय करते समय यथोचित परिश्रम की कमी का संकेत मिला। सामग्री संगठनों में औसत मांग अनुपालन लगभग 70 प्रतिशत था। ऊपरी स्टॉक स्तर से ज्यादा सामग्री

संगठनों द्वारा ₹7359.37 करोड़ के मूल्य की इन्वेंट्री रखी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप भंडारों की खराबी और अप्रचलन से संबंधित जोखिम के साथ प्रतिवर्ष ₹588.75 करोड़ की इन्वेंट्री वहन की लागत का दायित्व हुआ।

(अध्याय-II)

II. भारतीय नौसेना में पोतों एवं पनडुब्बियों की दुर्घटनाएं

एकपोत/पनडुब्बी की हानि भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, क्योंकिनएपोतों/पनडुब्बियोंकेअधिग्रहणमेंआठसेदसवर्षोंसेअधिककीखरीद/निर्माणप्रक्रियाशामिलरहतीहै।इसलिए, यहअनिवार्यहैकिभारतीयनौसेनाशांतिकेसमयमेंदुर्घटनाओंसेअपनीसंपत्तिकोमुक्तरखे।2007-2008 और 2015-16 केबीच, भारतीयनौसेनाकेपोतोंऔरपनडुब्बियोंमेंमुख्यरूपसेआग/विस्फोट/बाढ़केकारण 38 दुर्घटनाएंहुई।इनदुर्घटनाओंमेंदोनौसैनिकपोतोंऔरएकपनडुब्बीकेअलावाबहुमूल्यजीवनकीहानिहुई।भारतीयनौसेनाकीस्थापनाकेबादसे, सुरक्षाकेमुद्दोंसेनिपटनेकेलिएकोईसंस्थागतरूपरेखानहींहै।सुरक्षामुद्दोंसेनिपटनेकेलिएभारतीयनौसेनाद्वाराएकसमर्पितसंगठन 2014 मेंस्थापितकियागयाथा, हालांकि इसके लिएसरकार की संस्वीकृति प्रतीक्षित है।

(पैराग्राफ 3.1)

III. समुद्री गैस टर्बाइन की ओवरहॉल सुविधा की स्थापना

आई॰एन॰एस एक्सिला 1991 से एम3ई जी॰टीज़ का ओवरहॉल कर रहा है, लेकिन जी॰टीज़ के ओवरहाल के पूरा होने में अन्य बातों के साथ-साथ, पुर्जों और जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण असामान्य विलंब का सामना करना पड़ रहा है। एम-15 जी॰टीज़ के ओवरहॉल के लिए आवश्यक सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं, हालांकि इस सुविधा को स्थापित करने की योजना 1986 के बाद से की गई थी। इस बीच, 1241 आर॰ई श्रेणी के बारह पोतों में से दो, जिनमें एम-15 जी॰टीज़ को काम में लाया जाता था, को अप्रैल 2016 तक सेवामुक्त कर दिया गया था। 2008 में नियोजित एम-36 जी॰टीज़ के लिए ओवरहॉल की सुविधा में उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्यों के बीच समकालीनता की कमी के कारण देरी हुई। परिणामतः, नौसेना जी॰टीज़ के ओवरहाल के लिए ओ॰ई॰एम पर आगे भी निर्भर रही, जिसमें ₹317.77 करोड़ का व्यय हुआ। लम्बी अवधि के लिए मानवशक्ति को न रखने के कारण, आई॰एन॰एस एक्सिला तकनीकी दक्षता की अपर्याप्त उपलब्धता से जूझ रही है।

(पैराग्राफ 3.2)

IV. यू.एच-3एच हेलीकॉप्टरों का संचालन और रखरखाव

लैंडिंग प्लेटफार्म डेक के एक अभिन्न अंग के रूप में खरीदे गए हेलीकॉप्टरों के यू॰एच-3एच बेड़े, स्क्वाड्रन की चार से तीन हेलीकॉप्टरों की यूनिट स्थापना में कमी के बावजूद सात में से छः वर्षों में इसकी सेवाकारिता के वांछित स्तर को बनाए रखने में असमर्थ थे। स्पष्ट लक्ष्यों के अभाव में, डेक आधारित उड़ान काफी कम रही। समर्पित डिपो स्तर की रखरखाव सुविधाओं के न होने और पुर्जों की अनुपलब्धता का बेड़े के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण की कमी के कारण नौसेना रखरखाव, मरम्मत कार्य और रसद मुद्दों के लिए विदेशी मरम्मत एजेंसी पर लगातार निर्भर है।

(पैराग्राफ 3.3)

V. पेरिस्कोपोंकीस्थापना के विलम्ब के कारण सिन्धुघोष वर्ग कीपनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग

पेरिस्कोपों की आपूर्ति के लिए आवश्यक विक्रेता के स्वामित्व में विस्तार के संबंध में अनुबंध में संशोधन करने कीमंत्रालय की अनुमति प्रदान करने मे की गयी 34 महीनों से अधिक की देरी के कारण पेरिस्कोपों की आपूर्ति करने तथा सिन्धुघोष वर्गकी पनडुब्बियों की स्थापना करने में विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप अगले रीफिट तक 22 से 62 महीनों के लिए पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग किया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

VI. अनिवार्य तंत्र की स्थापना न करने के कारण विमानों की उड़ान सुरक्षा से समझौता

भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक के विमानों पर एक महत्वपूर्ण उड़ान सुरक्षा उपकरण की अनुपलब्धता ने विगत 12 वर्षों से उनका सुरक्षित परिचालन प्रभावित किया। उपकरण की सुपुर्दगी समयावधि एवं विमान पर उसकी स्थापना में तालमेल न होने के कारण और चार वर्षों के लिए भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, एक विमान बेड़े का सेवामुक्ति को संज्ञान में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹5.58 करोड़ की लागत पर 10 उपकरणों की अधिक खरीद हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

VII. ऑफसेट दायित्व के फलन में देरी के कारण बेड़े के टैंकरों का भेद्य होना

बेड़े के टैंकरों की,2011 में उनकी सुपुर्दगी से लेकर, रक्षा प्रणालियों की अनुपलब्धता ने उनकोवाह्य खतरों के प्रति भेद्य बना दिया। इसके साथ, दो बेड़े के टैंकरों की संविदा के ऑफसेट खंडके अन्तर्गत ली जाने वाली महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति/स्थापना से भुगतान का संबंध नहोने केपरिणामस्वरूप विदेशी विक्रेता को ₹26.73 करोड़ का समयापूर्व भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

VIII. दिल्ली क्षेत्र में नौसैनिक अधिकारियों द्वारा लघुशस्त्र-फायरिंगअभ्यास की कमी

सभी भारतीय नौसेना कार्मिकों से अपेक्षित है कि उन्हें सभी प्रकार के लघु शस्त्रों के संचालन की प्रक्रिया का ज्ञान हो। यह देखा गया कि दिल्ली क्षेत्र में अभ्यास फायरिंग में नौसैनिक अधिकारियों का कवरेज़ कम था जो लघु-शस्त्रों के संचालन में उनकी योग्यता के बारे में चिन्ताजनक था।

(पैराग्राफ 3.7)

IX. एक हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए एयरो इंजन की अवांछित अधिप्राप्ति

भारतीय नौसेना ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दो हेलीकॉप्टरों के लिए चार एयरो इंजनों की अधिप्राप्ति का आदेश देते समय, अनुबंध करने से पूर्व किफ़ायती मरम्मत से परे (बी॰ई॰आर) घोषित एक हेलीकॉप्टर तथा ओवरहॉल के पश्चात प्राप्त 16 एयरो इंजनों को ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि, इन अधिक इंजनों को बाद में पाँच हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति में मिला लिया था, तथापि एक अन्य हेलीकॉप्टर की बी॰ई॰आर घोषणा के परिणामस्वरूप तीन

एयरो इंजनों की इन्वेन्ट्री धारिता उनके अनुमोदन से अधिक हो गई तथा इन तीन अधिक एयरो इंजनों की अधिप्राप्ति पर ₹16.62 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

X. एक पोत निर्माणी को विदेशी विनिमय दर में अन्तर के कारण ₹5.23 करोड़ का अनियमित भुगतान

भारतीय तटररक्षक ने संविदागत प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण विदेशी विनिमय दर में अन्तर के रूप में मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा को ₹5.23 करोड़ का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 4.1)